

प्रेषक,

सुभाष कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवार्थ,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 4 फरवरी, 2009

विषय:- नै0 एमीनेन्ट इन्फाडेवलपर्स प्रा0लि0 को ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु ग्राम बढेड़ी तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में कुल 5.90 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-368/भूमि व्यवस्था, दिनांक-26.05.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नै0 एमीनेन्ट इन्फाडेवलपर्स प्रा0लि0 को ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु ग्राम बढेड़ी तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में कुल 5.90 है0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-154 (2) एवं उत्तराखण्ड, (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा। भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन (ग्रुप हाउसिंग योजना) के लिए करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है।

यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गयी भू कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के लिये वैध होगी।

7- आवास विभाग के शासनादेश संख्या-1942/5/आ0-2006 -115/2006 दिनांक-17.8.2006 एवं इसके क्रम में जारी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था आवास विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था से ही निर्माण कार्य कारायेगी तथा कलस्टर, नेबरहुड एवं टाउनशिप विकास हेतु मार्ग निर्देशिका से सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों का काढाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

8- चूंकि भूमि पर निर्माण कार्य कराये जाने से जनित जन सुविधाओं एवं अवस्थापनाओं पर दबाव की प्रतिपूर्ति एवं भरपाई हेतु भूमि उपयोग तथा भविष्य में क्षेत्र के बाह्य अवस्थापना विकास के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-459/४/आ0-2006-115 (आ)/2006 दिनांक-20.02.2007 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भू-उच्चीकरण शुल्क राजकोष में जमा किया जायेगा।

9- सम्बन्धित संस्था द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु वांछित समस्त अवस्थापना सुविधाये अपने स्तर से उपलब्ध करानी होगी इसके सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर ही मानचित्र स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी तथा इस हेतु सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाएगा।

10- स्थल पर निकटवर्ती क्षेत्र में प्रचलित महायोजना के अनुसार ही पहुँच मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।

11- भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों/विनियमों में भवनों की ऊँचाई, भू आच्छादन, एफ0ए0आर0, भू गेह पार्किंग सम्बन्धी मानकों में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-2269/5/आ0-2007-55 /आ0/2006 दिनांक-6.11.2007 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

- 12- सम्बन्धित इकाई द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेंसी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु किया जायेगा।
- 13- किसी दशा में प्रस्तावित कंटाओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 14- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 15- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियों/स्वीकृतियों प्राप्त कर ली जायेगी।
- 16- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने, भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०- /समदिनांकित/ 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- एमीनेन्ट इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०, कारपोरेट कार्यालय 34, बाबर लेन, द्वितीय तल कनाट प्लेस नई दिल्ली।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(सन्तोष बड़ौनी)
अनु सचिव।